गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 204
दि. 25.11.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी फहराएंगे ध्वज, खास है यह भगवा ध्वज

(जीएनएस)।

अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा विजय ध्वजरोहरण करेंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वज केवल भगवान राम के प्रति भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि यह भारतीय अध्यात्म, इतिहास और अयोध्या की महान सूर्यवंश और रघुकुल परंपराओं का भी साक्षी बनेगा।

25 नवंबर को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ये ध्वजारोहण कर समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था।

भगवा ध्वज की क्या है खासियत?

यह विशेष ध्वज अहमदाबाद की एक कंपनी में बनाया जा रहा है। इसे पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से तैयार किया गया है, ताकि यह सूर्य की रोशनी, वर्षा और तेज हवा जैसी प्राकृतिक चुनौतियों का सामना कर सके। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है, जिसे मंदिर के शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे ध्वजदंड पर फहराया जाएगा।

तेज हवा और तेज धूप में भी खराब नहीं होगा ध्वज

ध्वजदंड को 360 डिग्री घूमने वाले चैंबर पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें बॉल बेयरिंग्स का उपयोग किया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि ध्वज तेज हवाओं में भी सुरक्षित रहे और फटे नहीं। नमी और तापमान के प्रभावों को कम करने के लिए ध्वज को खास तरीके से निर्मित किया गया है, जिससे यह सभी मौसमों में टिकाऊ बना रहे।

इस भव्य ध्वज को बनाने में चार से पांच कारीगरों ने दिन-रात काम किया है। यह तीन लेयर वाले सिल्क साटन से बना है, जिसमें अंदर की लाइनिंग भी है।

इसमें बारीकी से कढ़ाई की गई है, जो इसे एक बेहतरीन रूप और बनावट प्रदान करती है।

ध्वज में त्रेतायुग के तीन मुख्य प्रतीक 'ॐ', 'सूर्य' और 'कोविदार वृक्ष' अंकित हैं। ध्वज का केसरिया रंग धर्म, त्याग और साहस का प्रतीक है। सूर्य प्रतीक भगवान राम के सूर्यवंशी होने को दशार्ता है, जो शौर्य, तेज और पराक्रम की ऊर्जा का परिचायक है। वहीं, 'ॐ' सनातन संस्कृति के अध्यात्म, अनंतता और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है।कोविदार वृक्ष का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में, विशेष रूप से अयोध्या कांड में, कई बार मिलता है। यह प्रतीक त्रेता युग से जुड़ा है।

यह दिन पूरे देश में विवाह पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, ध्वजारोहण का यह भव्य समारोह अभिजीत मुहूर्त में होगा।

कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आज होगा प्रधानमंत्री मोदी का आगमन

(जीएनएस)।

हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को चिह्नित करने के लिए ज्योतिसर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेंगे।

हरियाणा सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर आज ज्योतिसर (कुरुक्षेत्र) में राज्यस्तरीय समागम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचकर गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य मंत्रीगण और गणमान्य अतिथि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

प्रधानमंत्री ज्योतिसर स्थित महाभारत अनुभव केंद्र का लोकार्पण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान पवित्र ब्रह्मसरोवर पर महाआरती में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को समागम स्थल का दौरा किया। उन्होंने मंच, संगत स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और आगंतुकों की सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए।

गुरु तेग बहादुर जी का अनुपम त्याग

धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध अपना शीश न्यौछावर किया। उनके श्रद्धालुओं भाई दयाला जी, भाई सती दास जी और भाई मती दास जी ने भी अद्वितीय बलिदान दिए। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आठ गुरु साहिबानों ने अपने चरण रखे हैं और प्रदेशभर में लगभग 28 ऐतिहासिक गुरुद्वारे उनकी स्मृतियों को संजोए हुए हैं।

ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण

प्रधानमंत्री मोदी ज्योतिसर में स्थापित अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र महाभारत की कथा, दर्शन और इतिहास को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जीवंत करता है। लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बने इस परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य शंख 'पांचजन्यह्न का भी लोकार्पण होगा।

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव

कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री पवित्र ब्रह्मसरोवर पर महाआरती में शामिल होंगे। दीपों की लौ, वेद मंत्रों की गूंज और आस्था की उमंग के बीच होने वाली यह महाआरती भारत की आध्यात्मिक विरासत और कुरुक्षेत्र की वैश्विक पहचान को और अधिक गौरवान्वित करेगी।

'वरना हाथ से निकल जाएगी मुंबई', मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आखिर क्यों दी इतनी बड़ी चेतावनी?

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुका है। इस चुनाव के संपन्न होने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव होंगे। चुनावों को लेकर राजनीतिक दल वोटरों को साधने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों से पहले मुंबई को लेकर बड़ी चेतावनी दे डाली है। राज ठाकरे के इस बयान के बाद चुनावी माहौल और भी गरमा गया है।

प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई को लेकर चेतावनी दे डाली है।

याद रहे इस बार ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां साथ में मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। हालांकि अभी इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं आगामी बीएमसी चुनावों को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई को लेकर चेतावनी दे डाली है।

मनसे प्रमुख राज ठाकने कहा, "यदि मराठी लोगों ने लापरवाही बरती, तो मुंबई उनके हाथों से निकल सकती है, और यह उनके लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकता है।" ठाकरे ने जोर देकर कहा, "आने वाले बीएमसी चुनाव मराठी मानुस के लिए निर्णायक होंगे। अगर हम सावधान नहीं रहे, तो मुंबई हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उसके बाद हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बिल्कुल भी लापरवाह न बनें।"

राज ठाकरे ने मुंबई के वोटरों से अपील की कि वे अपने आसपास सतर्क रहें। ठाकरे ने कहा, "आने वाले दिनों में मैं विस्तृत रूप से बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह समय संवेदनशील है, इसलिए लापरवाह न रहें। अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहें।

प्रधानमंत्री ने कबड्डी विश्व कप 2025 जीतने पर भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कबड्डी विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई दी। श्री मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में

कहा: 'कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को हार्दिक बधाई! खिलाड़ियों ने अद्भुत जज्बा, कौशल और समर्पण दिखाया है। उनकी यह जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी अपनाने, बड़ा सपना देखने और ऊंचा लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करेगी।

सीजेआई के शपथ ग्रहण से गायब रहे लाल किताब लेकर नजर आने वाले राहुल गांधी, भाजपा ने कसा तंज- जंगल सफारी पर होंगे

(जीएनएस)।

24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सीजीआई के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल न होने की भाजपा ने कड़ी आलोचना की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ना होकर डॉ. बी. आर. अंबेडकर और संविधान का "अनादर" किया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता पर देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उपस्थित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यक्रम को "छोड़ने और बहिष्कार" करने का आरोप लगाया। पूनावाला ने पत्रकारों से कहा कि "आज जब पूरा देश मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह का एक तरह से जश्न मना रहा था और मोदीजी के नेतृत्व वाली पूरी सरकार इस कार्यक्रम में मौजूद थी, तब उन्होंने इसे छोड़ दिया, इसका बहिष्कार किया।"

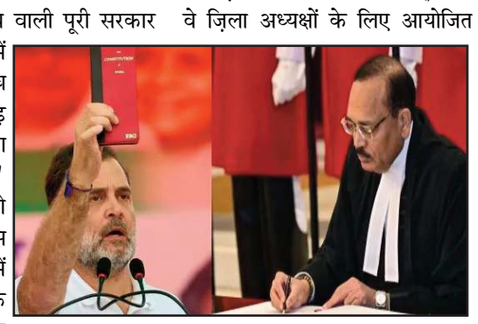

उन्होंने आगे टिप्पणी की, "इस गंभीर कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय, राहुल गांधी शायद किसी विदेशी यात्रा या जंगल सफारी पर होंगे।"

क्यों भाजपा ने जंगल सफारी का किया जिक्र?

बता दें कुछ दिन पहले नवंबर महीने में राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में जंगल सफारी पर गए, जहाँ वे ज़िला अध्यक्षों के लिए आयोजित कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए थे। बिहार चुनाव के दौरान इस यात्रा की भाजपा ने आलोचना की और उन्हें "पाटीर्बाजी का नेता" कहकर उनका मजाक उड़ाया था।

जस्टिस सूर्यकांत, जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और बिहार की मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई।

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी. आर. गवई के उत्तराधिकारी हैं और वे 9 फरवरी, 2027 तक इस पद पर रहेंगे।

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि गांधी और उनकी पार्टी लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक मानदंडों से ऊपर "परिवार तंत्र" को रखते हैं।

सीएम मोहन यादव ने किया तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ, बोले - 'कुआं चलकर प्यासे के पास आया है'

(जीएनएस)।

कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास का सबसे बड़ा संवाद शुरू हुआ। तीन दिवसीय राज्य स्तरीय पंचायत कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। मंच पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह लोधी समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

देश-विदेश में चर्चित इस सभागार में करीब डेढ़ हजार जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और चुनिंदा सरपंच एकत्र हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पंचायत प्रतिनिधियों को न केवल नई ताकत दी, बल्कि एक नया सपना भी दिखाया कि आने वाले दिनों में वे नई विधानसभा तक पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जिला पंचायत और जनपद पंचायत उपाध्यक्षों के स्कूल निरीक्षण को सार्थक बनाने का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब निरीक्षण सिर्फ कागजी नहीं रहेगा। उपाध्यक्ष जो कमियां रेखांकित करेंगे, उन्हें लिपिबद्ध किया जाएगा और कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। डॉ. यादव ने कहा, "आपकी रिपोर्ट अब फाइलों में नहीं दबेगी, उसका असर दिखेगा।"

उन्होंने पंचायतों को सशक्त बनाने की अपनी सोच को कबीर की पंक्तियों से जोड़ा। "धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय।" सीएम ने कहा कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन तीन दिन का यह खुला संवाद पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव रखेगा। उन्होंने सभागार के ऐतिहासिक महत्व को याद दिलाते हुए कहा कि 1956 से नई विधानसभा बनने तक यही विधानसभा थी। आज यहीं से शुरूआत है। आने वाले समय में आप सब नई विधानसभा तक पहुंचेंगे। यह मेरा वादा है।

सीएम ने गांवों को भारत की आत्मा बताते हुए कहा कि आदिकाल से हमारे समाज में स्वशासन की परंपरा रही है। पंचायतें अब सिर्फ योजनाएं लागू करने की इकाई नहीं रहेंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास के हर पैमाने को खुद तय करेंगी। उन्होंने कहा कि आज तक प्यासा कुएं के पास जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने कुआं चलकर प्यासे के पास पहुंचा दिया है। तीन दिन खुलकर अपनी समस्याएं बताइए। हर समस्या का समाधान यहीं निकलेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मंगलवार को नवसारी में राज्य के 13वें अत्याधुनिक बस पोर्ट का लोकार्पण करेंगे

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आम लोगों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त बस पोर्ट देने का अभिनव विचार मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में साकार हुआ
- 82 करोड़ रुपए के खर्च से 5025 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित अत्याधुनिक बस पोर्ट के लोकार्पण समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे मौजूद

गांधीनगर, 24 नवंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मंगलवार, 25 नवंबर को नवसारी में 82 करोड़ रुपए के खर्च से 5025 वर्ग मीटर क्षेत्र में नवनिर्मित अत्याधुनिक सुविधाओं वाले बस पोर्ट का लोकार्पण करेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य के बस अड्डों का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कायाकल्प करने का विजन दिया है, ताकि आम नागरिकों को भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त बस पोर्ट उपलब्ध हो सकें।

गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने राज्य में बनने वाले बस अड्डों को प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप आधुनिक

सुविधाओं से युक्त बस पोर्ट के रूप में विकसित करने का दृष्टिकोण अपनाया है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर बनने वाले ऐसे बस पोर्ट में यात्रियों की सुविधा के लिए डीलक्स वेटिंग रूम, आर.ओ. पानी की व्यवस्था, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रिफ्रेशमेंट के लिए कैंटीन, दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर की सुविधा और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब तक राज्य में ऐसे 12 बस पोर्ट बनाए गए हैं।

इतना ही नहीं, बड़े शहरों के बस पोर्ट में मूवी थियेटर, बैंक्वेट हॉल और शॉपिंग मॉल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल राज्य के 13वें बस पोर्ट का मंगलवार, 25 नवंबर की शाम पांच बजे नवसारी में लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल, राज्य के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री तथा नवसारी जिला के प्रभारी मंत्री श्री कनुभाई देसाई, आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल और परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माली सहित कई विधायक और सांसद उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सुविधा युक्त बस पोर्ट के निर्माण के चलते राज्य में पर्यटकों के लिए आरामदायक यात्रा अनुभव, व्यापारियों के लिए नए अवसर और युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार एवं करियर के लिए तथा छात्रों को पढ़ाई के लिए आवागमन की प्रभावी सार्वजनिक परिवहन सुविधा मुहैया कराने के साथ ही गुजरात एक महत्वपूर्ण ट्रैवल हब बन गया है।

सम्पादकीय

बिहार में बढ़ा सम्राट चौधरी का कद

सम्राट चौधरी को मिलना नीतीश सरकार के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के साथ ही शुक्रवार को बिहार की सत्ता में बड़ा परिवर्तन दिखा। 2005 के बाद से लगातार गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभाल रहे थे, जो आमतौर पर सभी मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं पर ताजा दायित्व बंटवारे में यह महत्वपूर्ण विभाग उनसे छीना गया है और गृहमंत्री अमित शाह के विश्वास पात्र सम्राट चौधरी को दिया गया है। इससे इन अटकलों को जोर मिला है कि बिहार पर भाजपा का पूरा नियंत्रण हो चुका है और नीतीश कुमार महज रिमोट मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाजपा की वर्षो से यही कोशिश रही कि बिहार का वंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। इसी उद्देश्य से चुनाव से पहले भाजपा ने यह घोषणा नहीं की थी कि नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के इस उद्देश्य की प्राप्ति में अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश आज भी सबसे कद्दावर नेता हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मजबूरी के चलते नीतीश को भाजपा की यह शर्त माननी पड़ी कि गृह विभाग उनके पास नहीं होगा, भाजपा अपने पास रखेगी और नीतीश को झुकना पड़ा। इस तरह अमित शाह के विश्वासपात्र सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री पद के साथ-साथ गृह मंत्रालय भी मिल गया। अगर यह कहा जाए कि अब नीतीश रिमोट मुख्यमंत्री हैं तो गलत शायद न हो। असल वंट्रोल तो दिल्ली से ही होगा। अब तमाम प्राशासन, पुलिस, कानून व्यवस्था इत्यादि सम्राट चौधरी के हाथ में होगी। बिहार में लालू राज समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार नवम्बर 2005 में सत्ता में आए। उसके बाद लगातार 20 साल से गृह विभाग उनके पास था। लालू राज के जिस जंगलराज की बात इस चुनाव में कानून व्यवस्था स्थापित कर दहशत के उस दौर को समाप्त किया और शांति व्यवस्था लागू करवाने में नीतीश का विशेष योगदान रहा। अपराध पर नकेल कसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, पुलिस को खुली छूट दी। सख्त कानून व्यवस्था के जरिए यह अवधारणा बनी कि अपराधी चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, सियासी दबदबा भी रखता हो, कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। सुशासन का प्रादेश में ऐसा माहौल बना कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू ही कहलाने लग गए। दो दशक के दौरान बिहार में कोई बड़ा दंगा भी नहीं हुआ। नीतीश कुमार को इस बार गृह विभाग न मिलना चौंकाने वाला जरूर है। लोग इसका मतलब तलाश रहे हैं। क्या भाजपा यह संकेत दे रही है कि मजबूरी के चलते नीतीश को मुख्यमंत्री तो बना दिया पर कितने दिन तक वह इस पद पर टिके रहेंगे इस पर अटकलों का बाजार गर्म है। पर शपथ ग्राहण से पहले नीतीश को यह समझा दिया गया था कि चूंकि भाजपा की सीटें जद(यू) से ज्यादा हैं इसलिए गृह विभाग तो हमारे पास ही रहेगा। नीतीश कुमार ने अपने पैरों पर पहले ही वुल्हाड़ी मार ली थी इसलिए इसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास शायद कोई और विकल्प नहीं रहा होगा। पर नीतीश मंझे हुए खिलाड़ी हैं वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। क्या निकट भविष्य में बिहार में कोई नया खेला भी देखने को मिल सकता है। वैसे भाजपा को गृह मंत्रालय मिलने से राज्य में अपराधियों पर तो नकेल कसेगी ही लेकिन यदि वैसा नहीं हुआ तो उसका असर भी उल्टा हो सकता है। गृह विभाग भाजपा को मिलने से पाटा विरोधियों खासकर आरजेडी और कांग्रेस में बेचैनी बढ़नी स्वाभाविक है। अंत में जन सुराज पाटा के संस्थापक प्राशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार की नईं वैबिनेट भ्रष्ट और अपराधियों से भरी है। यह मंत्रिपरिषद बिहार के लोगों के मुंह पर एक तमाचा है।

शिक्षा में सबसे बड़ा सुधार होने वाला है! क्या है हायर एजुकेशन बिल? क्या होगा आपके कॉलेज पर असर

(जीएनएस)।

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अगले कुछ महीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 पेश करने जा रही है। जिसके जरिए देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी।

इस बिल के तहत अलग-अलग संस्थाओं (UGC, AICTE, NCTE) को खत्म कर उन्हें एक ही कमीशन में जोड़ने का प्रावधान है। इसका मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ज्यादा फ्रीडम देना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। यह बिल न सिर्फ मौजूदा शिक्षा ढांचे को नया रूप देगा, बल्कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के कामकाज में भी बड़ा फेरबदल कर सकता है। इसे लेकर छात्र से लेकर शिक्षक तक सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर यह नया कानून उच्च शिक्षा का भविष्य कैसे बदलने वाला है।

- सरकार इस बिल के जरिए देश की तीन बड़ी संस्थाओं - UGC, AICTE और NCTE - को एक ही छतरी के नीचे लाने की तैयारी कर रही है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बार इसे NEP 2020 की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है।
- अभी तक देश में तीन अलग-अलग संस्थाएं उच्च शिक्षा को नियंत्रित करती हैं , UGC (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) जो सामान्य उच्च शिक्षा देखती है, AICTE (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे तकनीकी कोर्स संभालती है और NCTE जो शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े कोर्स की मान्यता तय करती है। लएउक बिल के तहत इन तीनों की जगह एक ही बड़ा रेगुलेटर बनाया जाएगा।
- इससे नियम एक जगह से बनेंगे और कॉलेजों को अलग-अलग एजेंसियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मेडिकल और लॉ की पढ़ाई इस बिल के दायरे में नहीं आएगी। मतलब, एक ही नियम, एक ही ढांचा और एक ही निगरानी तंत्र।
- लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक HECI Bill 2025 का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्त बनाना, पारदर्शी मान्यता प्रणाली लागू करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। सरकार इसे देश की शिक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े सुधार के रूप में पेश कर रही है।
- नया आयोग तीन काम करेगा-नियम बनाना, कॉलेजों की मान्यता और पढ़ाई के स्तर और गुणवत्ता के नियम। ध्यान रहे, फंडिंग अभी भी सरकार ही तय करेगी, लएउक के पास यह अधिकार नहीं होगा। NEP 2020 ने भी सुझाव दिया था कि ऊंची शिक्षा के लिए एक ही मजबूत रेगुलेटर होना चाहिए, जिससे व्यवस्था सरल और पारदर्शी हो सके। लएउक इ'' 2025 उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

संसद का शीतकालीन कब से कब तक? कितनी होगी बैठकें क्या-क्या होंगे मुद्दे, हर डिटेल

Winter Session: संसद का शीतकालीन कब से कब तक? कितनी होगी बैठकें क्या-क्या होंगे मुद्दे, हर डिटेल

☐ NEP 2020 का मॉडल: HECI के चार स्तंभ

नई शिक्षा नीति HECI को चार महत्वपूर्ण वर्टिकल्स में बांटती है ताकि पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।

1. National Higher Education Regulatory Council

मेडिकल और लॉ को छोड़कर सभी क्षेत्रों का नियमन करेगा।

2. National Accreditation Council

कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की मान्यता सुनिश्चित करेगा।

3. General Education Council

अलग-अलग कोर्सेज के learning outcomes तय करेगा।

4. Higher Education Grants Council

फंडिंग से जुड़ा काम देखेगा, हालांकि फैसले सरकार के हाथ में रहने की उम्मीद है।

NEP के मुताबिक HECI एक छोटा लेकिन प्रभावी निकाय होगा जिसमें ऐसे विशेषज्ञ होंगे जिनका सार्वजनिक सेवा में बेहतरीन रिकॉर्ड और अनुभव हो।

☐ बदलाव क्यों जरूरी बताया जा रहा है?

अभी की शिक्षा व्यवस्था पर अक्सर 'अत्यधिक नियंत्रण' और 'कई संगठनों की उलझन' जैसी शिकायतें होती रही हैं। कई बार कॉलेजों को अलग-अलग नियमों और अनुमतियों के जाल में फंसना पड़ता है। NEP 2020 ने भी माना था कि मौजूदा सिस्टम में अत्यधिक शक्ति कुछ संस्थाओं में केंद्रित है और जवाबदेही कम है। लएउक बिल एक पारदर्शी और सरल व्यवस्था बनाने का दावा करता है, जिससे संस्थान अधिक स्वायत्त और आत्मनिर्भर बन सकें।

☐ क्या आपके कॉलेज पर होगा असर?

अगर यह बिल पास होता है तो कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी, बेहतर ग्रेडिंग सिस्टम आने की संभावना है। कोर्स डिजाइन, सीखने के परिणाम और गुणवत्ता नियंत्रण केंद्रीकृत होंगे, कई पुराने नियम और अनुमति प्रक्रियाएं खत्म हो सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे कॉलेज 'स्व-शासित' बनेंगे और शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

☐ पहले भी हो चुका है ऐसा प्रयास - 2018 का विवादित बिल

साल 2018 में भी वक्ष्ठ को बदलने के लिए एक बिल लाया गया था, लेकिन उसमें अक्ठळए और ठउळए शामिल नहीं थे। उस बिल का भी उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को सरल बनाना था, पर उसमें लएउक को फंडिंग का अधिकार नहीं दिया गया था और कई फैसलों में केंद्र सरकार की भूमिका अत्यधिक बताई गई थी।

स्टेकहोल्डर्स ने तब इसका कड़ा विरोध किया था। चिंता यह थी कि इससे राज्यों का अधिकार कम होगा, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और पूरी प्रणाली 'अत्यधिक केंद्रीकृत' हो जाएगी।

☐ लएउक 2025 पर विपक्ष की चिंताएं क्या हैं

विपक्षी दलों, कई राज्य सरकारों और शिक्षा विशेषज्ञों ने कई बिंदुओं को लेकर सवाल उठाए हैं।

ज्यादा केंद्रीकरण का डरः कई लोग मानते हैं कि लएउक की संरचना में राज्यों की भूमिका कम होगी और केंद्र का नियंत्रण ज्यादा बढ़ जाएगा।

सामाजिक प्रतिनिधित्व पर सवालः 2018 में भी यह आरोप लगा था कि वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व लगभग नहीं के बराबर था।

फंडिंग पैटर्न में बदलाव की आशंकाः कुछ राज्यों ने चिंता जताई थी कि केंद्र की ओर से मिलने वाली 100% फंडिंग आगे जाकर 60:40 मॉडल में बदल सकती है।

राज्य और केंद्र के नियमों के बीच टकरावः संसदीय समिति ने भी कहा था कि नए बिल से राज्य विश्वविद्यालय दोहरे नियमों के बीच फंस सकते हैं।

बॉलीवुड के लिए दर्द भरा रहा 2025! धर्मेंद्र समेत इन कलाकारों ने कहा दुनिया से अलविदा

(जीएनएस)।

2025 में बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा के कई प्रतिष्ठित कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा, और उनके योगदान ने हमेशा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक अमिट छाप छोड़ी। आइए जानते हैं उन प्रमुख कलाकारों के बारे में जिनकी मौत 2025 में हुई, उनकी तारीख और उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।

1. मनोज कुमार -

4 अप्रैल 2025 दिग्गज अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार, जिन्हें 'भारत कुमार' के नाम से भी जाना जाता था, का निधन 4 अप्रैल 2025 को हुआ। वे सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे। 'उत्तम जीवन', 'कर्मभूमि' और 'दीवार' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय और निर्देशन ने उन्हें भारतीय सिनेमा का एक प्रेरणास्पद चेहरा बनाया। मनोज कुमार का निधन एक युग के अंत जैसा था, क्योंकि उन्होंने पीढ़ियों को फिल्मों के माध्यम से जागरूक किया।

2. मुकुल देव -

23 मई 2025 मुकुल देव, जिनका अभिनय फिल्मों और टेलीविजन दोनों में रहा, का निधन 23 मई 2025 को हुआ। उन्होंने 'सोनिया और अर्जुन', 'सत्यमेव जयते' जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। टीवी शो में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा, और उनके किरदार दर्शकों के बीच लंबे समय तक याद किए गए।

3. अच्युत पोतदार -

18 अगस्त 2025 वरिष्ठ अभिनेता अच्युत पोतदार का निधन 18 अगस्त 2025 को हुआ। वे अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, खासकर '3 इडियट्स' में उनके 'केहना क्या चाहते हो' संवाद ने उन्हें दर्शकों की आंखों में हमेशा के लिए बसाया। उनका अभिनय विनम्रता और सहजता का मिश्रण था, जो उन्हें हर पीढ़ी के दर्शकों के लिए प्रिय बनाता था।

4. पंकज धीर -

15 अक्टूबर 2025 टीवी और फिल्मों के जाने-माने अभिनेता पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर 2025 को हुआ। उन्हें सबसे अधिक 'महाभारत' में कर्ण के किरदार के लिए याद किया जाता है। उनका प्रदर्शन और स्क्रीन प्रजेंस ने उन्हें भारतीय टेलीविजन इतिहास में एक अमिट स्थान दिलाया।

5. गोवर्धन असरानी -

अमिताभ, शाहरुख से ज्यादा हिट फिल्में, फिर क्यों नहीं मिला धर्मेंद्र को 'सुपरस्टार का टैग'

(जीएनएस)।

24 नवंबर की सुबह 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र के निधन की खबर ने करोड़ों दिलों को झकझोर दिया। 8 दिसंबर को वह अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह करिश्माई सितारा आसमान में खो गया। छह दशकों से भी लंबी अपनी फिल्मी यात्रा में धर्मेंद्र ने रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और सीरियस किरदार दिए।

उन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं जीते, बल्कि कई पीढ़ियों के दिलों पर राज किया। अपने अब तक के जीवन में 75 से भी ज्यादा सुपरहिट फिल्मों के बावजूद, उन्हें कभी "सुपरस्टार" का तमगा नहीं दिया गया। जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी...

64 साल का करियर, 75 सुपरहिट फिल्म

80 के दशक में धर्मेंद्र ने अपने स्टारडम को एक नए मोड़ पर ले जाकर एक्शन फिल्मों की ओर रुख किया। इस दौरान कम बजट वाली कई फिल्में जैसे 'बदले की आग', 'घुलामी', 'लोहा', 'एलान-ए-जंग' बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। यही वह दौर था जब धर्मेंद्र को 'ही-मैन' कहा जाने लगा।

64 साल लंबे करियर में धर्मेंद्र ने कुल 75 सुपरहिट फिल्में दीं। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान या सलमान खान-सभी से ज्यादा हिट धर्मेंद्र ने अकेले दी हैं।

क्यों नहीं कहा गया 'सुपरस्टार'?

यह सवाल हमेशा से फैंस के मन में रहता है कि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद धर्मेंद्र को सुपरस्टार क्यों नहीं कहा गया। इसके पीछे कई वजहें हैं:

1. 70 के दशक में सोलो हीरों का ट्रेंड

धर्मेंद्र की कई मेगाहिट फिल्में- 'शोले', 'यादों की बारात', 'मेरा गाँव मेरा देश', 'धर्म वीर'-दो या अधिक हीरो वाली थीं। इस समय इंडस्ट्री का "सुपरस्टार" टैग दिलीप कुमार से राजेश खन्ना और फिर अमिताभ बच्चन जैसे सोलो एक्टर को मिल चुका था। जबकि धर्मेंद्र अक्सर एंसेंबल फिल्मों में दिखाई देते रहे।

2. 80 के दशक के सोलो हिट छोटे स्केल की फिल्में

802 में उनके सोलो एक्शन फिल्में हिट रहीं, लेकिन इनमें से कई कम बजट वाली थीं। वहीं अमिताभ बच्चन या विनोद खन्ना की फिल्में लगातार बड़ी बजट और बड़े कैनवास पर बनती थीं। इस वजह से धर्मेंद्र की फिल्मों का "मैग्निट्यूड" कम आंका गया।

3. खूब हिट, लेकिन फ्लॉप भी बहुत

धर्मेंद्र ने 6 ब्लॉकबस्टर, 7 सुपरहिट और कुछ दर्जन हिट फिल्में दीं। लेकिन वहीं, उन्होंने लगभग 150 फ्लॉप फिल्मों में भी काम किया-जो किसी भी टॉप स्टार में सबसे ज्यादा है। इस वजह से उनकी "सुपरस्टार" वाली छवि उतनी मजबूत नहीं बन पाई।

4. फिल्मों का ज्यादा साइन करना

धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा था, "मुझे फिल्में बहुत पसंद हैं। मैं मौका मिलते ही फिल्म साइन कर लेता हूँ। कई बार पता होता है फिल्म नहीं चलेगी, फिर भी मैं अपना 100% देता हूं। लोगों को मुझे एक्शन करते देखना पसंद है तो मैं क्यों रुकूं?"

बेटी की शादी में स्टेज पर झूम रहे स्मृति मंधाना के पिता, फिर ऐसा क्या हुआ कि आया हार्ट अटैक? डांस वीडियो वायरल

(जीएनएस)।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी उस वक्त टल गई, जब रविवार, 23 नवंबर को स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक के लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शादी का समारोह महाराष्ट्र में स्मृति के गृहनगर सांगली में होना था।

दुख की इस घड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें श्रीनिवास मंधाना को संगीत समारोह के दौरान डांस परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो दिखाता है कि शादी की खुशियां पूरे परिवार में कितनी उत्साह भरी थीं। एक अन्य वायरल वीडियो में स्मृति और पलाश मुच्छल भी बॉलीवुड हिट 'तेनु लेके' पर डांस करते नजर आए थे।

इस क्लिप को स्मृति की साथी खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने शेयर किया था। जिसमें बाद में जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटिल, यास्तिका भाटिया, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव सहित टीम के अन्य सदस्य भी शामिल हुए थे। स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने मीडिया को श्रीनिवास मंधाना के स्वास्थ्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह नाश्ते के दौरान मंधाना के पिता श्रीनिवास को तबीयत खराब महसूस होने लगी। जब हालत में सुधार नहीं हुआ, तो हमने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वह अभी निगरानी में हैं।

हेल्थ को लेकर डॉक्टर ने क्या कहा?

मिश्रा ने आगे कहा कि चूंकि स्मृति अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने फैसला किया है कि जब तक उनके पिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तब तक शादी स्थगित रहेगी। उन्होंने सभी से परिवार की निजता का सम्मान करने का आग्रह किया है। पारिवारिक डॉक्टर डॉ. नमन शाह ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे श्रीनिवास मंधाना को बाईं ओर सीने में दर्द हुआ, जिसे मेडिकल भाषा में 'एनजाइना' कहा जाता है। एउक्ष और अन्य रिपोर्ट्स में 'कार्डियक एंजाइम' बढ़े हुए पाए गए हैं, इसलिए उन्हें लगातार निगरानी में रखा जा रहा है।

महज 201 रनों पर ढेर हुई भारतीय टीम, कप्तान पंत से हुआ ब्लंडर, बल्लेबाजों ने किया सरेंडर

(जीएनएस)।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से बिखर गई। टीम इंडिया अपनी पहली पारी में मात्र 201 रन पर सिमट गई और फॉलोऑन बचाने के लिए जरूरी 289 रन भी नहीं बना पाई। हालांकि, साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने भारत को फॉलोऑन नहीं खिलाने का फैसला किया है और टीम फिर से बल्लेबाजी करेगी।

टॉप ऑर्डर फिर रहे फ्लॉप

भारतीय टीम की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही। 95 रन पर यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद टीम का पतन शुरू हो गया और स्कोर 122 रन तक आते-आते भारत ने सात विकेट गंवा दिए। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 58 रन की पारी खेली। केएल राहुल (22), साई सुदर्शन (15), कप्तान ऋषभ पंत (7), रवींद्र जडेजा (6) और नितीश रेड्डी (10) जैसे बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। ध्रुव जुरेल अपना खाता भी नहीं खोल सके।

क्ठऊ५२ रअ 1

वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने संभाला

जब टीम 122 पर सात विकेट गंवा चुकी थी, तब वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने मिलकर सातवें विकेट के लिए 72 रन की अहम साझेदारी की। सुंदर ने 92 गेंदों पर 48 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन वह अर्धशतक से चूक गए। उनके आउट होते ही भारतीय पारी 201 रन पर सिमट गई। साउथ अफ्रीका के लिए गेंदबाजी में ऑलराउंडर मार्को जानसेन ने कहर बरपाया। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले छह विकेट झटके और भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया।

जानसेन के अलावा साइमन हार्मर को तीन और केशव महाराज को एक विकेट मिला। पहले दो दिन गेंदबाजी करने और आधे दिन में बल्लेबाजी में ढहने के बाद अब भारतीय टीम को एक बार फिर गेंदबाजी के लिए उतरना होगा। साउथ अफ्रीका के पास पहली पारी के आधार पर 288 रनों की बड़ी बढ़त है, जिससे मैच पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई है।

पंत ने किया रिव्यू बर्बाद

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत का बल्लेबाजी प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में कप्तानी कर रहे पंत नंबर पाँच पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए। वह केवल आठ गेंदों पर सात रन बनाकर आउट हो गए। मार्को जानसेन की एक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। साउथ अफ्रीका की अपील पर अंपायर ने उन्हें तुरंत आउट दे दिया।

हालांकि, आउट होने के बाद, ऋषभ पंत ने तुरंत डीआरएस (DRS) लेने का फैसला किया। लेकिन रीप्ले में साफ हो गया कि गेंद ने उनके

नाती-पोतों से मिलने गए कनाडा गए दादा ने लड़कियों से की छेड़खानी, सरकार ने वापस खदेड़ा भारत!

(जीएनएस)।

भारत से आए एक नागरिक को सरनिया में दो किशोरियों का आपराधिक उत्पीड़न करने के आरोप में देश से निकाला जाएगा। 51 साल के जगजीत सिंह पर कनाडा में स्थायी रूप से दोबारा प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह जुलाई में अपने नवजात पोते से मिलने कनाडा पहुंचे थे।

हाई स्कूल के बाहर किशोरियों से की छेड़खानी

कनाडा पहुंचने के बाद सिंह सरनिया के एक स्थानीय हाई स्कूल के बाहर धूम्रपान क्षेत्र में अक्सर जाने लगे। पुलिस के अनुसार, 8 से 11 सितंबर के बीच उन्होंने बार-बार लड़कियों से संपर्क किया, उनसे ड्रग्स और शराब के बारे में बात करने की कोशिश की, और उनके साथ तस्वीरें लेने पर जोर दिया।

लड़कियों को जबरन पकड़ने की कोशिश

शिकायतकताओं में से एक ने बताया कि उसने पहले तस्वीर लेने से इनकार किया, लेकिन सिंह के हटने की उम्मीद में वह मान गई। आरोप है कि सिंह "उसके निजी दायरे में घुस आया" और उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, जिससे लड़की असहज हो गई और उसने उसे दूर धकेल दिया।

स्कूल छोड़ने के बाद भी किया पीछा

जांचकताओं ने बताया कि सिंह अंग्रेजी नहीं बोलता, फिर भी वह स्कूल परिसर छोड़ने के बाद भी छात्राओं का पीछा करता रहा। पुलिस ने उसे 16 सितंबर को गिरफ्तार किया और यौन उत्पीड़न एवं यौन हमले के आरोप लगाए। हालांकि उसे जमानत मिल गई, लेकिन दूसरी शिकायत आने के बाद उसे उसी दिन दोबारा गिरफ्तार किया गया।

ट्रांसलेटर न मिलने के कारण एक रात और हवालात में

दुभाषिए की अनुपलब्धता के कारण सिंह को एक रात और पुलिस हिरासत में रहना पड़ा। 19 सितंबर को उसने यौन उत्पीड़न के आरोप में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन आपराधिक उत्पीड़न के हल्के आरोप में दोषी माना।

जज ने कोर्ट में की तबीयत से खिंचाई

जस्टिस क्रिस्टा लिन लेजचिंस्की ने समय-सेवा की सजा स्वीकार की, लेकिन सख्त टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा, "आपको उस हाई स्कूल की संपत्ति में आने का कोई अधिकार नहीं था," और यह व्यवहार "बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

नौ दिन की कस्टडी, तीन साल का प्रोबेशन

विन्निपेग सन की रिपोर्ट के अनुसार, सिंह को नौ दिनों की प्री-प्ली कस्टडी के बराबर छोटी जेल की सजा और तीन साल के प्रोबेशन का आदेश दिया गया।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

भावनगर मंडल के 2 कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार से किया गया सम्मानित

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने मुंबई स्थित मुख्यालय में 11 कर्मचारियों को सम्मानित किया। इन कर्मचारियों ने अपने सतर्क कार्य से सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित किया। अक्टूबर-2025 माह में सतर्कता बरतने एवं संभावित घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन कर्मचारियों को जी.एम. संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया। सम्मानित कर्मचारियों में मुंबई सेंट्रल-2, वडोदरा-3, रतलाम-1, अहमदाबाद-2, राजकोट-1 एवं भावनगर मंडल से 2 कर्मचारी शामिल हैं। भावनगर मंडल से श्री दिलीप रजक (स्टेशन अधीक्षक - वांसजालिया) और श्री राम प्रसाद मीणा (ट्रैक मैंटेनर-रिबडा) को महाप्रबंधक संरक्षा

पुरस्कार (ऋृ रीं३८ अ६ं१) से सम्मानित किया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा कि वे सभी अनुकरणीय आदर्श हैं। कर्मचारियों की उच्च स्तर की प्रतिबद्धता एवं समर्पण ने सुरक्षित रेल संचालन में अहम भूमिका निभाई है। इनमें सुरक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों जैसे टूटे बोल्ट का पता लगाना, कोच/इंजन के नीचे धुआं एवं चिंगारी का पता लगाना, पटरियों में दरार, ट्रेन के कोचों का अलग हो जाना, टूटा कपलर बॉडी, डिब्बों में लटकते हुए सामान, स्टेशन पर लगे शुरूआती आग को बुझाना, खुले फाटक से पहले आपातकालीन ब्रेक लगाकर दुर्घटना रोकना आदि शामिल हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी एवं प्रशंसा कर भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य करते रहने हेतु प्रोत्साहित किया।

पश्चिम रेलवे सभी सम्मानित कर्मचारियों की त्वरित सोच एवं सतर्कता की सराहना करती है, जिनकी वजह से संभावित दुर्घटनाओं को टाला जा सका।

जामनगर को मिला सौराष्ट्र का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में 226 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित सौराष्ट्र के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया
- सुभाष ब्रिज से सात रास्ता सर्किल तक का नया रूट मिलने से नागनाथ जंक्शन, ग्रेन मार्केट, बेडी गेट जैसे क्षेत्रों में यातायात समस्या का निवारण होगा
- 3750 मीटर लंबे इस ब्रिज के अंडरस्पेस में 1200 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी तथा फूड जोन जैसी सुविधाओं का समावेश

गांधीनगर, 24 नवंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को जामनगर में 226.99 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सौराष्ट्र के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। सात रास्ता सर्किल से सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा तक के इस फोर लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज की लंबाई

4 एप्रोच सहित 3750 मीटर है। मुख्य ब्रिज फोर लेन 16.50 मीटर का है, जबकि इंदिरा मार्ग तथा द्वारका रोड एप्रोच टु लेन 8.40 मीटर के हैं। इस फ्लाईओवर ब्रिज के कारण जामनगर के नागरिकों को द्वारका, रिलायंस, नायरा, जीएसएफसी की ओर तथा राजकोट रोड की ओर आसान परिवहन सुविधा मिलेगी। इससे ब्रिज के नीचे स्थित मुख्य चार जंक्शनों सात रस्ता सर्किल, गुरुद्वारा जंक्शन, नर्मदा सर्किल तथा नागनाथ जंक्शन पर होने वाले यातायात जाम एवं दुर्घटना जैसी समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी, परिणामस्वरूप ईंधन व समय की बचत होगी।

इतना ही नहीं; सुभाष ब्रिज से सात रास्ता सर्किल होकर लाल बंगला सर्किल तक का नया रूट मिलने से नागनाथ जंक्शन, तीन दरवाजा (ग्रेन मार्केट), बेडी गेट जैसे क्षेत्रों में यातायात समस्या का निवारण होगा। इस विकास कार्य के साथ ही ब्रिज के नीचे स्थित अंडरस्पेस को भी नागरिक सुविधा के लिए विकसित किया गया है; जिसमें कुल 61 स्पेस में 1200 से अधिक वाहनों की पार्किंग व्यवस्था (850 टू-व्हीलर्स, 250 फोर-व्हीलर्स, 100 रिक्शा, 100 अन्य तथा 26 बस पार्किंग) शामिल है। इसके अलावा; कुल 4 स्पेस में पे एण्ड यूज टॉयलेट, 1 लोकेशन पर श्रमिक सुविधा केन्द्र (लेबर चौक), 10 स्पेस में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, 4 लोकेशन पर वेटिंग/सिटिंग की व्यवस्था और 4 लोकेशन पर फूड जोन की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे ने वडोदरा मंडल के तीन कर्मचारियों को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया

रेलवे के संचालन में संरक्षा सर्वोपरि होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी की सजगता एवं सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने वडोदरा मंडल के तीन रेल कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार अक्टूबर 2025 के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए सतर्कता दिखाने और संभावित दुर्घटनाओं को समय रहते टालने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रदान किए गए।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारी (1) श्रीमती परमार हेमलता, पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के करचिया में (फिटर-क),के पद पर कार्यरत हैं। एक वैगन को शेंकवेयर प्लेट के कारण सिक के रूप में चिन्हित किया गया था। वैगन पुनः वापस आने के बाद, श्रीमती हेमलता परमार ने उसी

वैगन में ८ड्ड्री टूटा हुआ पाया, जो समय पर न मिलने पर गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता था। उनकी सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी सुरक्षा समस्या टल गई।

(2) श्री एस. के. मल्ल रतनसिंह वागलाभाई मुढेल 'वडोदरा' में (ट्रेन मैनेजर), के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक11.10.2025 को लगभग 15:38 बजे, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 6 से रवाना हो रही थी, उन्होंने देखा कि एक यात्री जनरल कोच में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और अचानक फिसलकर कोच और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्रीमल्ल ने तुरंत ब्रेक प्रेशर छोड़कर ट्रेन को आपातकालीन रूप से रोका, जिससे एक संभावित जानलेवा दुर्घटना टल गई।उन्होंने पब्लिक और आरपीएफ स्टाफ की सहायता से घायल यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ को सौंपा। उनकी समय पर की गई कार्यवाही, सूझबूझ और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने एक अमूल्यजीवन की रक्षा की।

(3) श्री देवांग देसाई 'वडोदरा' में (एलपीएम), के पद पर कार्यरत हैं। दिनांक 23.10.2025, को पालनपुर - अहमदाबाद सेक्शन के बीच ट्रेन संख्या 16507 के पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी द्वारा फुट-प्लेटिंग निरीक्षण के दौरान, उनका कार्य उत्कृष्ट पाया गया।

टिहरी दुर्घटनाः गुजरात, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों के यात्रियों को लेकर पहुंची थी बस, मृतकों की लिस्ट आई सामने

(जीएनएस)।

गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत कर्नाटक के तीर्थ यात्रियों को लेकर टिहरी जिले के कुंजापुरी मंदिर में दर्शन को आई टूरिस्ट बस हादसे का शिकार हो गई है। बस नरेंद्रनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 29 यात्री सवार थे, जो देश के कई राज्यों के लोगों को लेकर कुंजापुरी मंदिर दर्शन के लिए आए हुए थे।

हादसे की खबर मिलते ही पूरा प्रशासन रेस्क्यू कार्य में जुटा रहा। बताया जा रहा है कि तीर्थ यात्री मां कुंजापुरी के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी अचानक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। मृतकों में चार महिलाएं व एक पुरुष शामिल हैं।

एसडीआरएफ से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को 12 बजे के आसपास थाना क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अंतर्गत कुंजापुरी-हिंडोलाखाल के पास एक बस के लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिरने की सूचना मिली। बस में 29 लोगों के सवार होने की संभावना बताई गई। सूचना पर एसडीआरएफ की कुल पांच टीमें तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर रेस्क्यू कार्य चलाया गया। हादसे में पांच लोगों की मौत हुई है।

जिनमें चार पुरुष और एक महिला शामिल है। तीन घायलों को एम्स ऋषिकेश और चार घायलों को श्रीदेव सुमन उप जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर में भर्ती कराया गया है। 17 लोग सामान्य है। मृतकों में दिल्ली, सहारनपुर यूपी, महाराष्ट्र, बैंगलुरु और गुजरात के लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के नरेंद्रनगर कुंजापुरी मंदिर के समीप हुई बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगतों को श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में घायलों को जिला प्रशासन और रऊक्क्ष द्वारा नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है, साथ ही गंभीर रूप से घायलों को अक्क्ष्टर ऋषिकेश रेफर किया गया है।

मृतक-

1- अनीता पत्नी नरेश चौहान नि0 222 द्वारिका दिल्ली। उम्र लगभग 50 वर्ष

2- आशु त्यागी पत्नी प्रदीप कुमार उम्र 51 वर्ष नि0 रणखंडी रोड ,धलौला सहारनपुर उ0प्र0।

3- नमिता प्रबोध काले उम्र 58 वर्ष नि0- 227 पुष्पक रामनगर कैम्पस यूनिवर्सिटी नागपुर महाराष्ट्र।

4- अनुजा वेंकटरमन पुत्री वेंकट उम्र 48 वर्ष नि0 बैंगलुरु।

5- पार्थ सारथी मधुसूदन जोशी पुत्र मधुसूदन जोशी उम्र 70 वर्ष नि0- ईशावास्लयम खत्री पोल , बाजवाडा, बडोदरा गुजरात।

भोपाल की 12वीं टॉपर साक्षी पर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जानिए कैसे आईएएस बनने की जिद में छोड़ा था घर

"मैं 2030 में आईएएस बनकर ही घर लौटूंगी" - यह वो नोट था जो भोपाल की बजरिया इलाके की रहने वाली 12वीं की मेरिट होल्डर साक्षी ने घर छोड़ते वक्त अपने कमरे में छोड़ा था। 92% अंकों के साथ स्कूल टॉप करने वाली साक्षी का एक ही सपना था - IAS बनना। लेकिन परिवार उसकी शादी तय कर चुका था।

महीनों की जद्दोजहद, समझाने-मनाने और दबाव के बाद जनवरी 2025 में साक्षी ने घर छोड़ दिया। मामला जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच ने देश में पहली बार ऐसा फैसला सुनाया जो लड़कियों की शिक्षा और सपनों के हक की मिसाल बन गया।

घर से भागने की पूरी कहानी

साक्षी (असली नाम गोपनीय) बजरिया थाना क्षेत्र की एक मध्यमवर्गीय फैमिली की बेटी है। 12वीं में 92 फीसदी अंक लाकर उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। कोचिंग जॉइन करने, दिल्ली या कोटा जाने की बात करती तो घरवाले टाल देते। पिता और बड़े भाई का साफ कहना था - "लड़की को इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं, शादी ही उसका भविष्य है।"\

साक्षी ने कई बार समझाया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन जब एक अच्छे घर से रिश्ता पक्का हो गया तो उसने फैसला ले लिया। जनवरी 2025 में एक सुबह वह घर से निकली और लौटकर नहीं आई। कमरे में सिर्फ एक नोट छोड़ा -"पापा, मैं IAS बनकर ही लौटूंगी। 2030 तक इंतजार करना। मुझे माफ कर देना।"

हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका, पुलिस की तलाश

परिवार ने पहले खुद ढूंढ़ा, रिश्तेदारों के यहां पूछताछ की। जब कुछ पता नहीं चला तो पिता ने हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने भोपाल पुलिस को सख्त निर्देश दिए। जांच में नोट मिला, फिर साक्षी के मोबाइल की आखिरी लोकेशन, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी सब खंगाले गए।

अंत में सुराग मिला - साक्षी ने इंदौर में अपना आधार कार्ड अपडेट कराया था। पुलिस ने पता लगाया कि वह अब 18 साल की हो चुकी है और इंदौर में एक छोटे से PG में रहकर कोचिंग कर रही है। उसे कोर्ट में पेश किया गया।

कोर्ट रूम में साक्षी ने जो कहा, सब सुनकर खामोश हो गए

जब जज साहब ने साक्षी से पूछा - "घर क्यों नहीं जाना चाहती?"

साक्षी ने बिना डरे, आंखों में आंसू भरकर कहाः "मैंने 92% अंक लिए। पूरा स्कूल मुझे सलाम करता था। लेकिन घर में सिर्फ एक बात थी - शादी। मैंने कहा था कि मुझे IAS बनना है। पापा ने कहा - लड़की को कअर बनने की क्या जरूरत? मैंने घर छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि अगर अब नहीं भागी तो जिंदगी भर पछताऊंगी। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, न अपनी, न अपने होने वाले पति की। मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूं।"

हाई कोर्ट का अनोखा और ऐतिहासिक फैसला

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच ने घंटों सुनवाई के बाद यह ऐतिहासिक आदेश दियाः

साक्षी अब बालिग है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे अपनी जिंदगी चुनने का पूरा हक है।

उसे जबरदस्ती घर नहीं भेजा जाएगा।

पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी। उसकी लोकेशन और पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

उज्जैन लोकायुक्त ने बैंक ऑफ इंडिया मनासा शाखा के सब स्टाफ को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया ट्रैप

(जीएनएस)।

लोकायुक्त पुलिस की सख्ती एक बार फिर रंग लाई। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के निर्देश पर उज्जैन लोकायुक्त इकाई ने सोमवार 24 नवंबर 2025 को नीमच जिले के मनासा में बड़ी ट्रैप कार्रवाई की।

बैंक ऑफ इंडिया की मनासा शाखा के सब स्टाफ रुपेश कौशल को 4.90 लाख रुपये के उद्यम क्रांति योजना (टरटए) लोन पास करने के एवज में 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी कार्रवाई बैंक की शाखा परिसर में ही हुई, जब आवेदिका आंचल नागदा ने रुपेश को नोट गिनवाकर दिए।

शिकायत कैसे आई और ट्रैप कैसे हुआ?

21 नवंबर 2025 को मनासा की रहने वाली आंचल नागदा (पिता लोकेश नागदा, पताः मकान नंबर 273, वार्ड नंबर 19, रामनगर कॉलोनी, मनासा) ने लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के एसपी आनंद यादव को लिखित शिकायत दी कि बैंक ऑफ इंडिया मनासा शाखा के सब स्टाफ रुपेश कौशल उनके उद्यम क्रांति योजना के 4.90 लाख रुपये के लोन को पास करने के लिए 15 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। शिकायत में आंचल ने बताया कि रुपेश ने साफ कह दिया था, "पैसे नहीं दोगी तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी।"

लोकायुक्त ने तुरंत कार्रवाई शुरू कीः

शिकायत का सत्यापन निरीक्षक हिना डाबर ने किया।

फोन पर हुई बातचीत में रुपेश ने फिर 15 हजार रुपये की मांग की, जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया।

सत्यापन सही पाए जाने पर 24 नवंबर को ट्रैप की योजना बनाई गई।

सोमवार दोपहर करीब 2 बजे 12 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने बैंक परिसर में घेराबंदी की। आवेदिका आंचल नागदा ने पहले से तय निशान वाले 15 हजार रुपये के नोट रुपेश कौशल को गिनवाकर दिए। जैसे ही रुपेश ने पैसे जेब में डाले, टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। नोटों पर लगा केमिकल पाउडर रुपेश के हाथों पर चमक उठा। पूरी कार्रवाई का वीडियो भी बनाया गया।

लोकायुक्त टीम के जांबाज

कार्रवाई का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक ने किया। टीम में शामिल रहेः

निरीक्षक हिना डाबर

श्याम शर्मा

अनिल ऑटोली

हितेश लालावत

उमेश जाटवा

इसरार सहित कुल 12 सदस्य

रुपेश कौशल पर क्या कार्रवाई?

रुपेश कौशल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(f), 13(2) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे उज्जैन लेकर आया जा रहा है। मंगलवार को विशेष न्यायालय में पेश किया जाएगा। बैंक मैनेजर से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या वे इस गोरखधंधे से अनजान थे या मिले हुए थे।

लोकायुक्त एसपी आनंद यादव का बयान

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन आनंद यादव ने बताया, "महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। यह इस महीने की चौथी बड़ी ट्रैप है। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी हो, रिश्वत लेते पकड़ा गया तो छोड़ा नहीं जाएगा। आम जनता से अपील है कि रिश्वत मांगने वालों की शिकायत करें, उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।"

नीमच-मनासा में हड़कंप

ट्रैप की खबर फैलते ही मनासा कस्बे में हड़कंप मच गया। बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय व्यापारियों ने कहा, "लोन के नाम पर बैंक वाले महीनों से परेशान करते हैं। आखिर कोई पकड़ा तो गया।" आंचल नागदा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, "मैं डर गई थी, लेकिन लोकायुक्त ने इतनी जल्दी कार्रवाई की। अब मेरा लोन भी जल्दी पास हो जाएगा।"

इस महीने उज्जैन लोकायुक्त की चौथी बड़ी कार्रवाई

4 नवंबरः नागदा में तहसीलदार 20 हजार रिश्वत लेते ट्रैप

11 नवंबरः बड़नगर में पटवारी 8 हजार लेते पकड़ा

18 नवंबरः उज्जैन में नगर निगम का बाबू 10 हजार लेते धराया

24 नवंबरः मनासा में बैंक सब

रिंग से उठकर बना लिया साम्राज्य! कुलदीप सिंह कीपा बने भारत के सबसे बड़े बॉक्सिंग प्रमोटर

(जीएनएस)।

कुलदीप सिंह कीपा ने राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज से भारत के सबसे प्रभावशाली बॉक्सिंग प्रमोटर बनने तक का सफर तय किया है। आज वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक मुकाबले आयोजित कर रहे हैं और भारतीय बॉक्सिंग प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर पहुंचा रहे हैं। बादियाला (बठिंडा) के निवासी और भारतीय सेना के पूर्व जवान कीपा ने 2008 में अपने पेशेवर बॉक्सिंग करियर की शुरूआत की थी।

लेकिन 2014 में सिर की चोट के कारण रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने तुरंत प्रमोशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में कदम रखा। यह निर्णय जिसने भारतीय प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पूरा परिदृश्य बदल दिया। अब तक कीपा सैकड़ों भारतीय बॉक्सरों का प्रबंधन कर चुके हैं और 50 से अधिक देशों अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ओशियानिया और एशिया में फाइटर्स के साथ व्यक्तिगत रूप से यात्रा कर चुके हैं।

उनके प्रबंधित फाइटर्स ने दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सिंग स्टार्स के साथ एक ही कार्ड पर मुकाबला किया है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है नीराज गोयत का मुकाबला, जब उन्होंने 15 नवंबर 2024 को माइक टायसन बनाम जेक पॉल के अंडरकार्ड पर ब्राजीलियाई स्टार विंडरसन नूनेस का सामना किया था।गोयत ने भारत-

मैक्सिको के ऐतिहासिक मुकाबले में जोस जेपेडा के खिलाफ भी हिस्सा लिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बॉक्सिंग पहचान और मजबूत हुई।

कीपा ने विश्वप्रसिद्ध प्रमोटरों जैसे बॉब एरम (टॉप रैंक), ऑस्कर डी ला होया (गोल्डन बॉय प्रमोशन्स), फ्रैंक वॉरेन (क्वींसबेरी प्रमोशन्स) और एडी हर्न (मैचरूम बॉक्सिंग) के साथ काम किया है। वे हइउ, हइअ, हइड, व्हड और व्हऋ जैसी सभी प्रमुख विश्व बॉक्सिंग संस्थाओं के साथ संबंध बनाए हुए हैं और 2014-15 से अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं।

प्रमोशन के अलावा कीपा ने भारतीय सिनेमा में भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने फ्फ्फ (राम चरण), मुक्काबाज (विनीत कुमार), तूफान (फरहान अख्तर), साला खडूस (आर. माधवन) और घनी (वरुण तेज) जैसी फिल्मों में बॉक्सिंग दृश्य कोरियोग्राफ किए और अभिनेताओं को प्रशिक्षण दिया।नीराज गोयत के मुकाबले के दौरान कीपा का प्रेरक पंजाबी भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उनके जुनून और अपने फाइटर्स के प्रति समर्पण स्पष्ट झलका।फिलहाल कीपा हर महीने भारतीय बॉक्सरों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर दिला रहे हैं।

वे दुनिया भर के प्रमोटरों के साथ सहयोग करके भारतीय प्रतिभाओं को लगातार मंच प्रदान कर रहे हैं।कुलदीप सिंह कीपा का कहना है, "मेरा मिशन भारतीय बॉक्सिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। हर फाइटर को विश्व मंच पर मौका मिलना चाहिए, और मैं इसे संभव बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित हूं।"ऐतिहासिक मुकाबलों और मिलियन-डॉलर फाइट्स का आयोजन कर, कुलदीप सिंह कीपा भारत को वैश्विक प्रोफेशनल बॉक्सिंग मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित कर रहे हैं।

कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में होगी हाथी की सफारी, जानिए कब, कहां, कैसे और कितने में होगी सफारी

(जीएनएस)।

जंगल सफारी रोमांच का शौक रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। टाइगर रिजर्व में नया रोमांच देखने को मिलेगा। कॉर्बेट और राजाजी में एलिफेंट सफारी को मंजूरी मिल गई है। जिसके बाद दिसंबर से ढिकाला बिजरानी जोन में हाथी सफारी का रोमांच देखने को मिलेगा।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से इस ठंड के सीजन में पर्यटकों के लिए खुशखबरी आई है। वर्षों से बंद पड़ी हाथी सफारी को आखिरकार फिर से अनुमति मिल गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता, रॉयल बंगाल टाइगर और रोमांचक जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध है।

वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पार्क में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी थी। उसी आदेश के बाद

हाथी सफारी पूरी तरह बंद कर दी गई थी।

जिसके बाद से कई लोगों पर रोजगार का संकट भी आ गया था। स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड की जून 2024 में हुई बैठक में इसके लिए हरी झंडी दी गई थी। विभागीय औपचारिकता पूरी होने के बाद अब इसे लागू किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार हाथी सफारी ढिकाला और बिजरानी, दोनों प्रमुख जोन में शुरू की जाएगी। दोनों जगह सुबह और शाम की शिफ्ट में हाथी सफारी होगी। ढिकाला में 2 हाथियों से सफारी कराई जाएगी और पर्यटकों के लिए दो रूट निर्धारित किए गए हैं। इन रूटों पर सफारी के दौरान पर्यटक रामगंगा नदी, घने जंगल, विशाल ग्रासलैंड और कई वन्यजीवों का बेहद नजदीकी अनुभव ले सकेंगे।

बिजरानी जोन में 1 हाथी के माध्यम से 2 रूट तय किए गए हैं। यहां भी दो घंटे की सफारी कराई जाएगी।

हाथी सफारी के टिकट पार्क के रिसेप्शन सेंटर से उपलब्ध होंगे। टिकट वितरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

भारतीय पर्यटकों के लिए ₹1000 प्रति व्यक्ति जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए ₹3000 प्रति व्यक्ति शुल्क तय किया गया है।

एक हाथी में अधिकतम बच्चों के साथ 5 लोग बैठ सकते हैं।

सफारी की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है।

प्लास्टिक मुक्त स्वदेशी मेलों से 'वोकल फॉर लोकल' को प्रोत्साहन

■ 2025 में राज्य के 16 शहरों में आयोजित स्वदेशी मेलों में 10 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ

■ मेलों में दो महीने के दौरान 40.50 लाख से अधिक लोग उमड़े

■ स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत के निर्माण का राजमार्ग है : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

गांधीनगर, 24 नवंबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नागरिकों से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए 'हर घर स्वदेशी' अभियान में उत्साहपूर्वक शामिल होने का आह्वान किया है। गुजरात में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में यह अभियान सफलतापूर्वक जारी है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन मे राज्य सरकार ने ग्रामीण कारीगरों, हस्त शिल्प कलाकारों और छोटे उद्योगों को समर्थन देने के लिए अनेक नई पहलें शुरू की हैं। 'गुजरात आत्मनिर्भर यात्रा', 'जी-मैत्री योजना' और 'महिला उद्योग सहाय योजना' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में स्वदेशी उत्पादों को एक नई ऊर्जा मिल रही है। राज्य में तहसील और जिला स्तर पर 'स्वदेशी मेला', 'वॉक फॉर स्वदेशी' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे जनजागरूकता

कार्यक्रमों का आयोजन कर इस अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप दिया गया है।

इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए शहरी विकास वर्ष 2025 के अंतर्गत राज्य के 16 शहरों में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया गया। 10 सितंबर से 31 अक्टूबर, 2025 के दौरान 16 शहरों में 'प्लास्टिक मुक्त' स्वदेशी मेले आयोजित किए गए, जिनमें 40.50 लाख से अधिक लोगों ने भ्रमण किया। इन मेलों में 10 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई। राज्य के भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, सूरत, वडोदरा, आणंद, गांधीधाम, मेहसाणा, मोरबी, नडियाद, नवसारी, पोरबंदर, सुरेन्द्रनगर और वापी में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया गया।

इन मेलों के आयोजन में महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और व्यवसायियों ने हिस्सा लिया।

540 स्वयं सहायता समूहों को 2707 स्टॉल आवंटित किए गए

इन मेलों में स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए 540 स्वयं सहायता समूहों को 2707 स्टॉल आवंटित किए गए थे। मेला भ्रमण करने आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए गेम शो, संगीत कार्यक्रम, लोक डायरा, पपेट शो (कठपुतली शो) और नाटकों का भी आयोजन किया गया था। आगंतुकों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। दिसंबर महीने में अहमदाबाद में स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले शॉपिंग फेस्टिवल के साथ ही आने वाले समय में नगर पालिका क्षेत्रों में स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए दृढ़तापूर्वक कहा है कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत के निर्माण का राजमार्ग है। आने वाले समय में देश का प्रत्येक नागरिक 'वोकल फॉर लोकल' का वाहक बनेगा और हर नागरिक स्वदेशी के मंत्र को आत्मसात करेगा। 2047 में जब भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाएगा, तब भारत अवश्य एक विकसित राष्ट्र होगा।

कौन हैं नरेंद्र नारायण यादव? नियुक्त किए गए बिहार का प्रोटेम स्पीकर, क्यों बेहद अहम है ये पद

(जीएनएस)।

नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 24 नवंबर (सोमवार) को नारायण यादव को स्पीकर पद की शपथ दिलाई है। स्पीकर बनने के बाद अब नरेंद्र नारायण यादव बिहार के नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 74 वर्षीय नरेंद्र नारायण देव आठवीं बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने आलमनगर सीट से जीत हासिल की है। इस चुनाव में उन्होंने वीआईपी उम्मीदवार नबीन कुमार को बड़े अंतर से हराया। नरेंद्र नारायण यादव ने 55,465 वोटों के प्रभावशाली अंतर से जीत दर्ज की।

कौन हैं नरेंद्र नारायण?

नरेंद्र नारायण यादव ने पहली बार 1955 में आलमनगर सीट से विधायक के रूप में चुने गए थे और तब से लगातार इसी सीट से जीतते आ रहे हैं। नरेंद्र नारायण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। यादव पहले भी बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

आजमनगर में नारायण यादव का है एक छत्र राज

आलमनगर विधानसभा सीट पर

1995 के बाद नरेंद्र नारायण यादव इस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। जनता दल और फिर जेडीयू के टिकट पर लगातार आठ बार विधायक बनकर रिकॉर्ड बनाया।

1952 के पहले चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के तनुका लाल यादव विधायक बने।

1957 से 1972 तक कांग्रेस के यदुनंदन झा और विद्याकर कवि ने लगातार पांच बार यहां से चुनाव जीता।

1977 से 1990 के बीच बीरेंद्र कुमार सिंह ने जनता पार्टी, लोकदल और जनता दल के टिकट पर लगातार चार बार इस सीट पर कब्जा जमाया था।

1995 से जेडीयू के नरेंद्र नारायण ने इस सीट पर कब्जा जताया है।

प्रोटेम स्पीकर की मुख्य जिम्मेदारियां

बिहार विधान सभा में प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है, लेकिन उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।

विधानसभा के नए कार्यकाल की शुरूआत में, प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित विधायकों को सदस्यता की शपथ दिलाते हैं।

जब तक स्थायी स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता, सदन की प्रारंभिक कार्यवाही प्रोटेम स्पीकर के अधीन ही चलती है।

स्थायी स्पीकर के चुनाव/चयन की पूरी प्रक्रिया का संचालन भी वही करते हैं।

जैसे ही शपथ ग्रहण पूरा हो जाता है, सदन की शुरूआती बैठकें- जब तक स्थायी स्पीकर न चुन लिए जाएँ-प्रोटेम स्पीकर ही संचालित करते हैं।

शुरूआती बैठकों में सदन का अनुशासन, प्रक्रिया, और मयार्दा बनाए रखना प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी होती है।

कई बार नए विधायक पहली बार सदन में आते हैं; प्रोटेम स्पीकर उन्हें सदन की प्राथमिक कार्यप्रणाली से अवगत कराने की भूमिका भी निभाते हैं।

नए कार्यकाल की शुरूआत से जुड़े आवश्यक कागजी औपचारिकताओं को पूरा कराने में भी प्रोटेम स्पीकर की भूमिका होती है।

होटल, उद्योग और किसानों की साझेदारी आपसी विकास के लिए महत्वपूर्णः सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी

(जीएनएस)।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने आज आतिथ्य उद्योग से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के साथ प्रत्यक्ष, संरचित और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सहयोग अपरिहार्य हैं।

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) द्वारा आयोजित एफपीओ-आतिथ्य और किसान लाभ शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यक्ष एफपीओ-होटल संपर्क एक हर तरह से शक्तिशाली और जीत के मॉडल का निर्माण करेगा - जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, जबकि होटलों को प्रीमियम, बड़े पैमाने पर रसायन मुक्त सामग्री प्राप्त करने में सुविधा।

डॉ. चतुर्वेदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में अब लगभग 40,000 एफपीओ हैं, जिनमें से कई ऐसे उत्पाद पेश करते हैं जो आतिथ्य क्षेत्र की स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ भोजन की बढ़ती माँग के अनुरूप हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को अभी भी, खुदरा कीमतों पर वस्तुएं खरीदना लेकिन थोक मूल्य पर उत्पाद बेचना—एक उलटे मूल्य निर्धारण चक्र का सामना करना पड़ रहा है। एक असंतुलन जिसे होटलों के साथ सीधी खरीद साझेदारी के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के कृषि-उद्योग सहयोग को मजबूत करने के आह्वान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी

साझेदारियां बिचौलियों को कम करेंगी, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करेंगी, किसानों के लाभ को बढ़ाएंगी तथा आतिथ्य क्षेत्र को सकल घरेलू उत्पाद में योगदान और रोजगार बढ़ाने में सक्षम बनाएंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती, जीआई-टैग उत्पादों और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, तथा केरल के कुमारकोम मॉडल को टिकाऊ उद्योग-समुदाय एकीकरण के लिए एक मानक के रूप में उद्धृत कर रही है।

शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं महानिदेशक, श्री सुमन बिल्ला ने कहा कि भारत को एक तेज-तर्रार, संरचित किसान-होटल साझेदारी ढाँचे की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा मॉडल सरकार के दृष्टिकोण को गति प्रदान करेगा और साथ ही ग्रामीण आजीविका को उन्नत करेगा और पर्यटन-संचालित मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा।

एफएचआरएआई के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल ने निरंतर आपूर्ति और गुणवत्ता-आश्वस्त होने पर एफपीओ से सीधे खरीद करने के लिए होटलों की तत्परता की पुष्टि की।

एचएआई के महासचिव श्री एमपी बेजबरुआ ने व्यापक विकास अवसरों को खोलने के लिए होटलों को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया।

उद्घाटन सत्र के दौरान उद्योग जगत के नेताओं श्री राहुल मैकरियस (विन्धम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स), श्री विश्वप्रीत सिंह चीमा (लेमन ट्री होटल्स) और सुश्री अंकिता जायसवाल (एचआरएएनआई एंड यूपीएचआरए) ने भी अपने विचार साझा किए।

खाद्य लेखक श्री सौरीश भट्टाचार्य द्वारा संचालित तकनीकी सत्र में राष्ट्रीय फार्म-टू-हॉस्पिटैलिटी आपूर्ति श्रृंखला के क्रियान्वयन के लिए एक स्पष्ट परिचालन खाका प्रस्तुत किया गया।

तकनीकी सत्र के दौरान प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल थेः

सुश्री आशा सोता (एमओएएफडब्ल्यू),

श्री विजय प्रताप सिंह आदित्य(एकगाँव ग्रुप)

श्री कीर्ति प्रसन्ना मिश्रा (इकोशिएट कंसल्टेंट्स),

श्री अश्विनी कुमार गोयला (रेडिसन होटल समूह),

सुश्री मीना भाटिया (ले मेरिडियन, नई दिल्ली),

और शेफ दविंदर कुमार और शेफ राकेश सेठी

यह ढांचा, आतिथ्य आपूर्ति श्रृंखला के साथ किसानों को एकीकृत करने के लिए भारत के पहले संरेखित, बहु-हितधारक राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट में से एक है।

शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण एफएचआरएआई द्वारा आयोजित प्रदर्शनी थी जिसमें 17 राज्यों के 50 एफपीओ शामिल हुए। प्रदर्शनी में क्षेत्रीय और जीआई-टैग वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई - जिनमें पीली चाय, कश्मीरी मामरा बादाम, हिमालयी केसर, मखाना, काली हल्दी, वन शहद, कतरनी चावल और कंधमाल हल्दी शामिल हैं।

बुर्का पहनकर संसद पहुंचने वाली सांसद कौन हैं? हुलिया देख घबराए बाकी एमपी, आखिर क्यों किया महिला नेता ने ऐसा?

(जीएनएस)।

ऑस्ट्रेलिया की धुर-दक्षिणपंथी सीनेटर पॉलिन हैनसन ने सोमवार को संसद में बुर्का पहनकर प्रवेश किया। उनका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम परिधान पर प्रतिबंध लगाने की मांग को जोर देना था। जैसे ही वह सदन में पहुंचीं, मुस्लिम नेताओं और सीनेटरों ने इसे नस्लवादी कृत्य बताते हुए कड़ी निंदा की।

विधेयक पेश न करने देने पर उठाया विवादित कदम

यह दूसरी बार था जब हैनसन ने बुर्का का उपयोग विरोध के रूप में किया। उन्होंने यह कदम तब उठाया जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बुर्का और अन्य पूरे चेहरे ढकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति नहीं मिली। इसके जवाब में उन्होंने बुर्का पहनकर संसद कक्ष में ही विरोध जताया।

सीनेट में हंगामा और कार्यवाही स्थगित

जैसे ही वह बुर्का पहनकर सीनेट चैंबर में पहुंचीं, सदन में हंगामा शुरू हो गया। जब उन्होंने बुर्का उतारने से इनकार किया, तो कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सीनेटर पॉलिन हैनसन को संसद भवन में बुर्का पहने हुए प्रवेश करते हुए देखा गया, जिससे माहौल और गरम हो गया।

मुस्लिम सीनेटरों ने बताया अपमानजनक

ग्रीन्स पार्टी की न्यू साउथ वेल्स से मुस्लिम सीनेटर मेहरीन फारूकी ने घटना को खुला नस्लवाद बताया। उन्होंने कहा, "यह एक नस्लवादी सीनेटर है, जो blatanntly नस्लवाद का प्रदर्शन कर रही है।" वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की स्वतंत्र मुस्लिम सीनेटर फातिमा पेमैन ने इस कदम को "अपमानजनक" करार दिया।

सरकार और विपक्ष-दोनों ने की निंदा

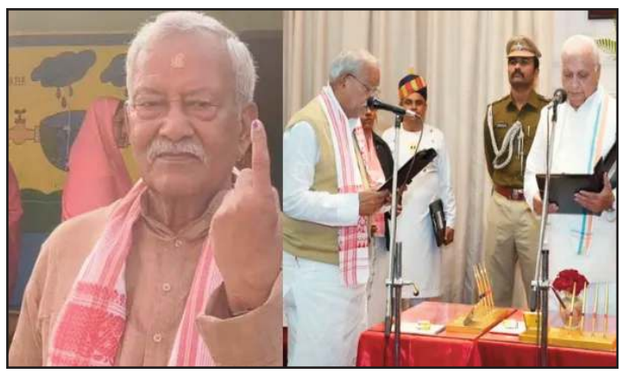

ऑस्ट्रेलिया की केंद्र-वामपंथी लेबर सरकार की सीनेट नेता पेनी वोंग और विपक्षी गठबंधन की उप-सीनेट नेता ऐनी रस्टन ने भी हैनसन के व्यवहार की निंदा की। वोंग ने इसे "सीनेट के सदस्य के योग्य आचरण नहीं" बताते हुए उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। हैनसन ने जब सदन छोड़ने से इनकार किया, तो कार्यवाही रोकनी पड़ी।

हैनसन की पुरानी राजनीति और विवादित इतिहास

क्वींसलैंड से सीनेटर हैनसन पहली बार 1990 के दशक में एशियाई आप्रवासन और शरणार्थियों के कड़े विरोध के कारण चर्चा में आई थीं। उनका राजनीतिक करियर इस्लामिक परिधान और मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध अभियानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2017 में भी संसद में बुर्का पहना था और उस समय भी राष्ट्रीय प्रतिबंध की मांग की थी।

वन नेशन पार्टी को बढ़ता समर्थन

हैनसन की वन नेशन पार्टी के पास सीनेट में चार सीटें हैं। धुर-दक्षिणपंथी आप्रवासन-विरोधी नीतियों को मिले समर्थन की वजह से पार्टी ने मई के आम चुनाव में दो नई सीटें हासिल कीं, जिससे उनका रुख और आक्रामक हो गया।

अ'२ड्ड फीं

उंल्लंः नाती-पोतों से मिलने गए कनाडा गए दादा ने लड़कियों से की छेड़खानी, सरकार ने वापस खदेड़ा भारत!

उंल्लंः नाती-पोतों से मिलने गए कनाडा गए दादा ने लड़कियों से की छेड़खानी, सरकार ने वापस खदेड़ा भारत!

फेसबुक पोस्ट में दी अपनी कार्रवाई की वजह

संसद से बाहर आने के बाद, हैनसन ने फेसबुक पर बयान जारी कर कहा कि उनका कदम सीनेट द्वारा उनके विधेयक को खारिज करने के विरोध में था। उन्होंने लिखा, "अगर संसद इसे प्रतिबंधित नहीं करेगी तो मैं इस दमनकारी, कट्टरपंथी, गैर-धार्मिक सिर के परिधान को संसद के पटल पर लाऊंगी।"

उन्होंने दावा किया कि बुर्का "राष्ट्रीय सुरक्षा और महिलाओं के दुर्व्यवहार का जोखिम" है।

हैनसन ने आगे कहा-"अगर वे नहीं चाहते कि मैं इसे पहनूं, तो बुर्के पर प्रतिबंध लगा दो।"

नए लेबर कोड को लेकर मजदूर संगठन क्यों कर रहे हैं विरोध, इस पर संविधान क्या कहता है

(जीएनएस)।

भारत सरकार ने हाल ही में देशभर के लगभग 40 करोड़ कर्मचारियों के लिए लेबर कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। पहले मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़े 29 अलग-अलग कानून थे, जिन्हें अब मिलाकर केवल चार लेबर कोड बना दिए गए हैं।

सरकार कहती है कि इन कोड के लागू होने से कर्मचारियों को कई तरह की राहत मिलेंगी लेकिन इन दावों के बावजूद नए लेबर कोड का देशभर में विरोध हो रहा है। मजदूर संगठनों का कहना है कि यह बदलाव कर्मचारियों के बजाय कंपनियों और मालिकों को फायदा पहुँचाएगा।

नया लेबर कोड क्यों हो रहा विवाद?

बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कई बड़े मजदूर संगठन-जैसे इंटक, एटक और सीआईटीयू-नए लेबर कोड का भारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन नियमों की वजह से कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी और मालिकों को मनमानी करने का ज्यादा अधिकार मिल जाएगा।

संगठनों का सबसे बड़ा आरोप 'फिक्स्ड टर्म जॉब' मॉडल पर है। उनके मुताबिक कर्मचारी को स्थायी नौकरी का कोई भरोसा नहीं होगा। इससे नौकरी की अनिश्चितता बढ़ेगी और मजदूर हर समय असुरक्षा में रहेंगे।

मजदूरों को सबसे ज्यादा डर

हड़ताल से जुड़े नियमों में बदलाव से है। अब अगर कोई संगठन हड़ताल के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। यूनियन की मान्यता भी रद्द हो सकती है।

इतना ही नहीं, हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को जेल या भारी जुमार्ने का सामना भी करना पड़ सकता है। पहले जरूरी सेवाओं से जुड़े मजदूरों के लिए हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देना होता था, लेकिन अब 60 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य कर दिया गया है। मजदूर संगठन कहते हैं कि हड़ताल मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार होता है और अगर इसे कमजोर कर दिया जाएगा तो मालिकों की मनमानी और बढ़ जाएगी।

क्या कहता है संविधान ?

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में मजदूरों, रोजगार, ट्रेड यूनियनों और श्रमिक कल्याण जैसे विषय समवर्ती सूची में आते हैं। इसका मतलब यह है कि इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। नए लेबर कोड पूरे देश पर लागू होंगे, लेकिन राज्यों को भी अपने-अपने नियम बनाने होंगे। इसलिए इन नए कानूनों को लागू करने में राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी होगी।

भारत में कुल 50 करोड़ से ज्यादा कामगार हैं, जिनमें से लगभग 90 फीसदी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। नए कोड इन सभी पर लागू होते हैं। मजदूर संगठनों का कहना है कि इस सुधार से मजदूरों के मौलिक अधिकार कमजोर हो जाएंगे, खासकर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह बदलाव अधिक नुकसानदेह साबित हो सकता है।

पुराने 44 कानून बनाम नए चार कोड

भारत में मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद कुल 44 कानून बनवाए थे। इन कानूनों ने कर्मचारियों को कई अधिकार दिए थे-जैसे निर्धारित काम के घंटे, यूनियन बनाने का अधिकार, सामूहिक बातचीत के नियम जैसे प्रावधान शामिल थे।

लेकिन नए कोड लागू होने के बाद मजदूर संगठनों का आरोप है कि 15 पुराने कानून खत्म कर दिए गए और जो बचे उन्हें मिलाकर ऐसा कानून बनाया गया है जो मजदूरों की जगह मालिकों के हित में ज्यादा दिखता है। नए प्रावधान मालिकों के हित में रखे गए उनके मुताबिक नए नियमों से मजदूरों के अधिकारों में कटौती दिखाई देती है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पहले किसी भी फैक्टरी में अगर 100 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे और मालिक उसे बंद करना चाहता था तो उसे सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी।

नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के सामने आने वाली बड़ी कानूनी चुनौतियां, कौन-कौन से केस की करेंगे सुनवाई?

(जीएनएस)।

भारत को आज 24 नवंबर को अपना नया चीफ जस्टिस मिल गया है जस्टिस सूर्यकांत । राष्ट्रपति ने उन्हें देश का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है और वे पूर्व उखक बीआर गवई की जगह संभाल रहे हैं । उनका कार्यकाल भले ही सिर्फ 14 महीने का हो, लेकिन इन 14 महीनों में उनके सामने देश के कई बड़े संवैधानिक और विवादित मामले आने वाले हैं, जो आने वाले समय में भारतीय न्यायपालिका की दिशा तय कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जस्टिस सूर्यकांत कई संवैधानिक मामलों की बेंच का हिस्सा रहे हैं। आर्टिकल 370 की वैधता को बरकरार रखने वाले ऐतिहासिक फैसले पर उनकी बेंच ने ही मुहर लगाई थी। पेगासस जासूसी मामले में भी वे उस बेंच में शामिल थे जिसने जांच समिति बनाने का निर्देश दिया था और कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते।

बिहार रक्क्र मामले में भी उन्होंने वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। कई अहम मामलों में वे सामाजिक न्याय, प्रशासनिक सुधार और संवैधानिक संतुलन के पक्षधर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 14 महीने के कार्यकाल में CJI जस्टिस सूर्यकांत के सामने कौन-कौन से केस होंगे।

□ SIR और वक्फ एक्टः CJI सूर्यकांत के लिए पहली बड़ी चुनौती

देश इस समय 'रक्क्र प्रक्रिया' को लेकर उबल रहा है। कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है । नए उखक होने के नाते सूर्यकांत के

सामने यह सबसे पहला बड़ा संवैधानिक मुद्दा होगा, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी होंगी।

इसी तरह वक्फ एक्ट से जुड़ा विवाद भी न्यायालय की चौखट पर है और इसका फैसला आने वाले वर्षों की सामाजिक और धार्मिक बहसों को प्रभावित कर सकता है।

□ तलाक-ए-हसन और दिल्ली-NCR प्रदूषणः जनता की उम्मीदें नए CJI से

दिल्ली-NCR में प्रदूषण लगातार गंभीर बना हुआ है और इस मसले पर कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है । अब इस मामले की अगली सुनवाई व फैसले पर सबकी नजरें सूर्यकांत पर होंगी।

तलाक-ए-हसन मामले की सुनवाई भी अहम मोड़ पर है । तीन महीने की अवधि में तीन बार तलाक बोलकर विवाह खत्म करने की इस प्रथा को चुनौती दी गई है। यह सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक संवैधानिक सवाल भी है और इसका फैसला सीधे करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा।

□ आर्टिकल 370 से लेकर AMU तक, उनके पुराने फैसले बताते हैं भविष्य की दिशा

जस्टिस सूर्यकांत ने कई ऐतिहासिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्टिकल 370 पर फैसला, बिहार SIR, धारा 144 की सीमाएं, जनजातीय अल्पसंख्यक अधिकार और दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत - इन सभी में उनकी कानूनी दृष्टि और संतुलित दृष्टिकोण नजर आता है। AMU के अल्पसंख्यक दर्जे जैसे संवैधानिक मुद्दों पर भी उनकी बेंच अहम भूमिका निभा चुकी है।

□ नए CJI, नया दौर - 14 महीने लेकिन चुनौतियां दशक भर जितनी बड़ी

जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल छोटा जरूर है, लेकिन इसमें आने वाले निर्णय भारत के संवैधानिक इतिहास में लंबी छाप छोड़ सकते हैं। पेगासस से लेकर प्रदूषण, रक्क्र से लेकर तलाक-ए-हसन और वक्फ एक्ट तक हर फैसला देश की राजनीति, समाज और प्रशासन पर गहरा असर डालने वाला है। भारत अब अपने नए CJI की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। आने वाले 14 महीने भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।

□CJI जस्टिस सूर्यकांत के बारे में अहम जानकारी

हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को जन्मे सूर्यकांत ने बहुत कम उम्र में अपनी पहचान बना ली थी। वे मात्र 38 साल के थे जब उन्हें हरियाणा का एडवोकेट जनरल बनाया गया। बाद में 2018 में वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत हुए। कानून की पढ़ाई उन्होंने एमडीयू रोहतक से की और 1984 में हिसार अदालत से वकालत शुरू की। फिर वे चंडीगढ़ चले गए और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे । 2004 में हाईकोर्ट के जज बने और उसके बाद से उन्होंने 300 से ज्यादा अहम फैसले दिए हैं।